

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 फरवरी 2026 — माघ 20, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक /LAW-42/308/2026/2026/21-ब/छ.ग./2026.—राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित तालिकाओं अनुसार कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित अधिवक्ताओं को कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित पद पर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त करता है—

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	Mr. Apoorv Kurup	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2	Mr. Atul Jha	
3	Mr. Rajat Nair	
4	Mr. Awadhesh Singh	
5	Mr. Bishwajit Dubey,	
6	Mr. Ravi Sharma,	

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	Mr. Praneet Pranav,	उप महाधिवक्ता
2	Mr. Vikrant Singh Bais,	
3	Mr. Suyash Pande	
4	Mr. Manu Chaturvedi	
5	Mr. Rishab Sahu,	

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	Mr. Apoorv Shukla	स्टैंडिंग कौंसिल
2	Mr. Prashant Singh,	
3	Miss Ankita Sharma,	
4	Mr. Abhishek Pandey,	
5	Miss Sugandha Jain	
6	Mr. Vinayak Sharma,	

अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता को देय फीस छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 4683/3812/21-B/2024 दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 तथा स्टैंडिंग कौंसिल को इस विभाग के आदेश क्रमांक 7077/1554/XXI-B/C.G./12 दिनांक 31.08.2012 के अधधीन होगी।

नियुक्त विधि अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे, परंतु विधि अधिकारी त्याग पत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार नियुक्त समस्त विधि अधिकारी, विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुरूप निम्नलिखित आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे:-

1. (अ) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।
(ब) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहां उनका पंजीयन हो, से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(स) उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया है।
(द) सात वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं।
2. प्राप्त घोषणा पत्र उक्तानुसार प्राप्त में उक्त संबंधित विधि अधिकारी की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे, यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग, मंत्रालय को सूचित करेंगे।
3. कृपया कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, प्रमुख सचिव.